

**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- अनीता मीना, आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या 6/2022 (राजसमन्द डिक्री)

1. रतनलाल पिता बाबरीलाल उर्फ बाबुलाल, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. बृजेश पिता बाबरीलाल उर्फ बाबुलाल, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. कंचन देवी पत्नी बाबरीलाल उर्फ बाबुलाल, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. बाबरीलाल उर्फ बाबुलाल पिता नाथूलाल जी, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्यामलाल पिता मोहनलाल जी, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. नाथूलाल पिता वरदीचन्द्र जी, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री गणेशलाल जी खटीक, निवासी हाल नातायत पति बाबरी उर्फ बाबुलाल खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती सुशीला पत्नी कैलाशचन्द्र जी, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. कैलाशचन्द्र पिता मोहनलाल जी, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. उप पंजीयक रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. पटवारी हल्का गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक
कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा प्रकरण संख्या 88/2019 दिनांक 03.02.2022

---/---

उपस्थित(वक्तबहस)

1. श्री आर.एल. रावत अभिभाषक अपीलान्तगण
2. श्री प्रकाश खटीक अभिभाषक रे. 1,2,3,5,6,7
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं0 4, 8, 9

---:---

निर्णय

दिनांक 06-02-2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्तगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) सपठित धारा 151 जा.दी. वास्ते न्यायालय आदेश की अवमानन बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया



कि आप न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 147/1998 आप न्यायालय द्वारा दिनांक 11-09-2001 को स्वीकार किया जाकर निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की गयी, किन्तु इसकी पालना अभी नहीं हो पायी है। इसलिए प्रार्थीगण ने आप न्यायालय में हकरसी प्रार्थना पत्र लगा रखा है, जिसके मुकदमा नंबर 1/16 होकर तारीख पेशी दिनांक 19-09-2019 नियत है। उक्त प्रकरण में निषेधाज्ञा की डिक्री पारित होने के बावजूद विपक्षीगण आपस में मिलकर बिना कानूनी विभाजन हुए न्यायालय आदेश की अवमानना करते हुए प्रार्थना पत्र वर्णित विवादित भूमियों में से आराजी नंबर 3064 को दिनांक 31-10-2014 को प्रेमी देवी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया, तत्पश्चात उसी दिनांक को प्रेमी देवी ने उक्त आराजी में से 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 6 को विक्रय कर दिया, जबकि उक्त स्थायी निषेधाज्ञा आदेश का विपक्षीगण को विधिवत ज्ञान था। विपक्षीगण ने आप न्यायालय के स्थायी निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद मौके पर बिना विधिवत विभाजन के निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तथा कब्जा करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना किये जाने से उनकी चल-अचल सम्पत्ति कुर्क कर नीलाम की जाकर उससे प्राप्त राशि राजकोष में जमा करायी जावे तथा विपक्षीगण द्वारा जो अवैध निर्माण किया जा रहा है उसे तुरन्त रूकवाया जाकर सिविल कारावास की सजा दिलायी जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में विपक्षीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध पेश किया गया है, क्योंकि आदेश 39 नियम 2क का प्रार्थना पत्र आदेशों पर लागू नहीं होता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर लागू होता है तथा वाद अथवा प्रकरण न्यायालय में पेण्डिंग होना आवश्यक है, जबकि इस प्रकरण में वाद दिनांक 11-09-2001 को निर्णित हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 03-02-2022 से विपक्षीगण का आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्तगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04-03-2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 व 5 से 7 की ओर से वकील श्री प्रकाश खटीक उपस्थित हुए, जबकि औपचारिक पक्षकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 4, 8 व 9 की ओर से राजकीय

अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11-09-2001 को पारित निर्णय व डिक्री का बिना अवलोकन किये आनन-फानन में मात्र रेस्पोंडेन्ट को सुनते हुए उक्त आदेश पारित किया है। रेस्पोंडेन्ट द्वारा जो आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह दावे पर लागू होता है, जबकि अपीलान्त का प्रार्थना पत्र अवमानना का था, जो दावे की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03-02-2022 निरस्त किया जावे तथा रेस्पोंडेन्टगण न्यायालय आदेश की अवहेलना किये जाने से उनकी चल-अचल सम्पत्ति कुर्क की जाकर उसके द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को रूकवाया जावे तथा सिविल कारावास की सजा दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में स्पष्ट अंकित किया है कि “जहां प्रकरण में वादग्रस्त भूमि से संबंधित मूल वाद का निस्तारण होकर डिक्री जारी हो चुकी हो वहां आदेश 39 नियम 2क सी.पी.सी. की कार्यवाही न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।” उक्त आधारों पर रेस्पोंडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर अपीलान्तगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क सी.पी.सी. खारिज किया है जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03-02-2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06-02-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर